प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

मार्च २०२४ • वर्ष-विंशति (२०) • अंक ०३ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०

चीफ इंजीनियर बरेली जोन श्री सतीश चंद्र नेगी जी के साथ
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई ।

RRKS Union Orgnished Karykarta Jodo Abhiyaan At Nad Mumbai

General Body Meeting at DRDL KARMIK SANGH HYDERABAD

Vice President Sri H Maruti Pawar, conducted Meeting With
SQAE(A) EMPLOYEES UNION AND WORKER UNION OF BADMAL

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

प्रिय मित्रों

आप सभी बन्धुओं को और आपके परिवार जनों, तथा इष्ट मित्रों को रंगों का त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आप सभी के जीवन में नया जोश और उत्साह लेकर आये। कुछ ही दिनों में भारतीय नव वर्ष विक्रमी सम्वत 2081 प्रारंभ होगा। भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं।

मित्रो आप सभी को ज्ञात है कि सदस्यता सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। हम एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने में सफल हुए। हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में सफल हुए। इसके लिये भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन के सभी कार्य कर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में आप सभी के प्रयासों से ही हमें यह सफलता प्राप्त हुई है। हमें अब क्रमांक 1 की ओर अपने कदम बढ़ाने है। इसके लिये आवश्यक है कि हमें जिन प्रतिष्ठानों में यूनियन नहीं है वहां पर नई यूनियन का गठन करना है। अगले तीन वर्षों में यदि हम 100 नई यूनियन स्थापित करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में क्रमांक 1 पर होंगे। हमें नई यूनियन के साथ अपनी पुरानी यूनियन पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को ठीक करना होगा। हमें अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा। हमें हर समय इस मूड में रहना है जैसे कल ही सदस्यता सत्यापन होना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे हर समय चुनाव मोड में रहते है। ऐसा ही जुनून हमारे कार्य कर्ताओं में भी आना चाहिये।

मित्रो हमें एक–एक विभाग की समीक्षा करनी होगी। हमें एक एक यूनियन की समीक्षा करनी होगी, तभी हम पूर्ण रूपेण सफल होंगे। हमें देखना होगा कि हम कहाँ आगे बढ़े और कहाँ पीछे गए। इस पर विचार करना होगा और यह भी विचार करना होगा कौन से कारणों से पीछे रह गए उनमें सुधार करना होगा।

Ofb के परिणामों पर विचार करना होगा कि हम क्यों दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर गए। हम केवल 180 वोट और लाये होते तो निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर होते। कुछ स्थानों पर हम 2 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत वोट कम पाए वहाँ पर कुछ सुधार हुआ होता तो आज नजारा ही कुछ और होता। GC 2010 में भी 7 स्थानों पर JCM4 से बाहर थे अब हम 13 स्थानों पर JCM से बाहर हो गए। कही कही हम कुछ ही वोट के कारण JCM 4 से बाहर हुए, वहां पर और मेहनत करनी होगी। JCM4 की ofb की डिस्ट्रिब्यूटशन सीट देखने से बहुत कुछ समझ मे आ रहा है। इसलिये एक एक यूनियन की समीक्षा करना जरूरी है ताकि हम आगे आने वाले समय में सुधार कर सकें बहुत से स्थानों पर हम JCM की 2 सीट में से 1 ही बचा सके। बहुत स्थानों पर हम अपनी 4 सीट JCM4 में बचाने में सफल हुए। बहुत से स्थानों पर हमारी सीटे JCM4 में बढ़ी कुछ स्थानों पर 2 या चार वोट की कमी से हम सीट नहीं बढ़ा सके। कृपया हम सभी को संकल्प लेना है और समीक्षा करके आगे बढ़ना है।

मित्रो हम सभी जानते है कि देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों के चुनाव के बाद मतगणना 4 जून को सम्पन्न होगी और 15 जून तक नई सरकार का गठन होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे सभी पेंडिंग मुद्दे अपनी जगह पर स्थगित हो गए। हम उम्मीद करते थे कि सरकार NPS को लेकर कुछ ठोस निर्णय चुनाव से पूर्व लेगी लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। आठवें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार ने फिलहाल चुप्पी नहीं तोड़ी जो हमारे लिये थोड़ा कष्टदायक है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता होने के नाते हम कभी निराश नहीं होते। हमें नई सरकार गठन होने के तुरंत बाद सरकार को अपना मांग पत्र देना होगा और आगे की लड़ाई शुरू करनी होगी। सरकार कोई भी हो भारतीय मजदूर संघ हर सरकार के साथ रेस्पॉन्स कॉपरेशन के साथ काम करते है।

सरकार जितना हमें सहयोग करेगी हम उतना ही सरकार को सहयोग देंगे यह भारतीय मजदूर संघ शुरू से कहता आ रहा है।

मित्रों आप सभी की जानकारी में है कि नेशनल कौंसिल JCM के घटक संगठनों ने घोषणा की थी कि वह 19 मार्च को NPS को रद्द कराने हेतु हड़ताल का नोटिस देंगे और 1मई से अनिश्चित कालीन स्ट्राइक पर जायेंगे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ हड़ताल का पूरी तरह से सफल बनाने हेतु कृतसंकल्प था। परन्तु हमेशा की तरह एक बार फिर NJCA ने कर्मचारियों को धोखा दिया। जैसे सातवें, छठे ,पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हड़ताल की धमकी दी और बिना कुछ प्राप्त किये सरकार की गोद में बैठ गये ऐसे ही एक बार फिर से सरकार की हाँ में हाँ करते नजर आ रहे है जैसा कि आपने लखनऊ की अपनी मीटिंग में सरकार की प्रशंसा करते उनको देखा है। एक तरफ इनके कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लड़ाई केवल वही लड़ सकते ऐसा प्रचार करते है और दूसरी तरफ इनके नेता इनकी मीटिंग में देश के रक्षा मंत्री महोदय को चुनाव में जिताने की बात करते स्पष्ट सुनाई देता है। सरकार कोई भी हो इन दोनों संगठनों को (इंटक और लाल झंडे) को सरकार की दलाली ही करनी है। जबकि भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मत है सरकार चाहे जो हो वह कर्मचारियों का अहित करेगी संस्थानों का अहित करेगी हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। यही हमारे और उनके बीच अंतर है।

❒

पुण्य स्मरण – स्व. गोविन्दराव आठवले जी

– श्रीराम ना. बाटवे
संरक्षक – भा. प्र. म. संघ

दि. 23 फरवरी 2024 को दोपहर 1:30 बजे स्व. गोविन्दराव आठवले जी के निधन की वार्ता मुझे विदर्भ प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष/महामंत्री श्री रमेश पाटिल जी द्वारा सर्वप्रथम मुझे दी गई।

यह समाचार सिर्फ मेरे समान छोटे कार्यकर्ता को ही नहीं अपितु भा. म. संघ से जुड़े हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा आघात था। हम सभी ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिन्हें भा. म. संघ का सम्पूर्ण इतिहास ज्ञात था।

23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद भा. म. संघ की प्रथम कार्यकारिणी में स्व. गोविन्दराव जी को मंत्री पद / उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिला था। स्व. गोविन्दराव जी रा. स्व. संघ से जुड़े होने के कारण उनके अंदर उनमें संघटन जोड़ने का कौशल था, उसके कारण ही उन्हें शायद यह दायित्व मिला था ऐसा मुझे लगता है।

भा. म. संघ का संविधान तैयार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अधिवक्ता होने के कारण उनका श्रमक्षेत्र में अच्छा सम्मान था। करीब 40 वर्ष अधिवक्ता के रुप में उन्होंने कई कामगारों के उजड़ते हुए घर को बसा दिया। उनकी एक विशेषता थी कि उनका जिनके साथ सम्पर्क हुआ उनके साथ उनका रिश्ता पक्का हुआ और इसी रिश्ते को उन्होंने संघटन के लिये उपयोग में लाया। भा. म. संघ का इतिहास उन्हें ज्ञात था और जिस आवश्यकता को देखते हुये भा. म. संघ का निर्माण हुआ उस राष्ट्रभावना को ध्यान में रखते हुये उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रांतों में भा. म. संघ के यूनियन हर उद्योग में कैसे बनें, इसके लिये अत्यन्त परिश्रम किया। रा. स्व. संघ के प्रथम बंदी के समय उन्हें 37 दिन कारावास भी हुआ। उनका वाचन बहुत था और एक अच्छे वक्ता तथा एक अच्छे लेखक होने के कारण अपने जीवनकाल में 30 से 40 किताबें भी लिखीं।

1972 में महाराष्ट्र विधान परिषद के ग्रेजुएट कॉन्स्टीट्यूएन्सी में विजय प्राप्त की और वे Member of Legislative Council (MLC) बनें। वहाँ भी उन्होंने उद्योग और श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए परिश्रम किया।

स्व. गोविन्दराव जी हमेशा श्रमिकों के बारे में ही सोचते थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ उन्होंने B.M.S. की यूनियनें बनाने के लिये प्रयास न किया हो। रेलवे, डिफेन्स, पोस्टल, परिवहन, ए. जी. (Accountant General) आदि सभी जगह भा. म. संघ की यूनियनें बनायी।

जहाँ तक डिफेन्स की यूनियनों के गठन का प्रश्न था उन्होंने ही दिन–रात एक कर परिश्रमपूर्वक जवाहरनगर भंडारा, ऑ. फै. चांदा, ऑ. फै. अम्बाझरी और पुलगांव डिपो में अपने संघटन खड़े किये। ऑ. फै. जवाहरनगर में श्री दाणी एवं प्रकाश सिंह विष्ठ, औ. ऑ. फै. चांदा में श्री जनार्दन अय्यर, श्री बेले, ऑ. फै. अम्बाझरी श्री एम. के. पाल, श्री जी. पी. त्रिपाठी एवं श्री एम. जी. कानिटकर, पुलगांव डिपो में श्री देशमुख कल्याण जी लाकड़े आदि लोगों से हमेशा संपर्क रखते हुए संघटन खड़े किये।

वे हमेशा कहते थे कि भा. म. संघ को समझने के लिये श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन समझना आवश्यक है और जिनसे उन्होंने प्रेरणा पायी वे परम पूज्य डॉ. हेडगेवार व परम पूज्य गुरु जी के जीवन को समझना चाहिये।

अपने उद्बोधन में वे कहते थे ''हम व्यक्तिपूजक नहीं हैं, अवश्य ही आदर्श व्यक्ति के चित्र को पुष्पमाला चढ़ाते हैं, किन्तु उस समय हम तस्वीर पर लगे कांच, लकड़ी के फ्रेम, चित्र पर बनी रेखायें, रंग या रुप की पूजा नहीं करते, अपितु उस व्यक्ति के गुणों की पूजा करते हैं।

मैंने उन्हें हमेशा पितृस्थान पर माना था, वे मा. विष्ठ जी, स्व. उहाके जी या मैं स्वयं उनसे मिलने नहीं जा पाये तो वह हमें स्वयं टेलीफोन कर या किसी के द्वारा पत्र भेजकर बुलाते थे और भा. म. संघ से सम्बन्धित बातें, संगठन और कार्यकर्ता ही उनकी चर्चा का प्रमुख केन्द्र रहता था। मेरे स्वभाव के कारण वे मुझे भा. म. संघ के अंदर का कम्युनिस्ट है ऐसा कहते थे। अभी वर्तमान में 12 जनवरी 2024 को मैं जब उनसे मिलने गया उन्होंने सहज रुप से मुझसे बोल गये ''श्रीरामजी अब ऊपरवाले को मुझे बुला लेना चाहिये'' शायद ये उनके अंदर की व्यथा थी। मैंने उसपर उन्हें कहा हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा जितना जीने के लिए उन्होंने हमें धरती पर भेजा है उतने दिन जिस हाल में हो हमें यहाँ रहना ही है। उस वक्त मुझे भी कभी ख्याल नहीं आया कि यह पितृ तुल्य छत्र हमसे भगवान जल्द छीनने वाले हैं।

29 फरवरी 2024, गुरुवार (माघ कृ. पंचमी) को उम्र के 95 वर्ष पूरे कर हम सबको अकेला छोड़कर वे निजधाम चले गये। उनके निधन के कारण भा. म. संघ के हर एक कार्यकर्ता बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक अपने ही परिवार का पितृतुल्य व्यक्तिभाव हमने खोया है। उनके जाने से सिर्फ भा. म. संघ ही नहीं अपितु कामगार क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, किन्तु परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो लिखा गया है वह तो होकर ही रहेगा।

मैं व्यक्तिगत रुप से एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ परिवार के हर एक सदस्य की ओर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उन्हें चिरशांति प्रदान करें।

ऐसे पितृतुल्य गोविन्दराव आठवले जी को मैं आप सबकी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

ॐ पूर्णमद, पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णभादाय, पूर्ण मेवा वशिस्यते

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॐ

❐

होली महोत्सव – भारतीय मजदूर संघ की नजर से

– शिवेन्द्र सागर शर्मा
मीडिया प्रभारी – भा. प्र. म. संघ

परिचय :

रंगों का जीवंत त्योहार होली, भारत में गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत के आगमन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक है। हालाँकि, अपने सांस्कृतिक उत्सवों से परे, होली का उत्सव भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिक आंदोलन की चिंताओं और आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इस अन्वेषण में, हम भारत में होली त्योहार के बहुमुखी आयामों पर प्रकाश डालते हैं, जैसा कि भारतीय मजदूर संघ की दृष्टि के माध्यम से देखा और अनुभव किया गया है, जो श्रम अधिकारों, सामाजिक न्याय और सामुदायिक एकजुटता के लिए जोर देता है।

ऐतिहासिक संदर्भ :

होली की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से प्रह्लाद और होलिका की कथा से होती है, जो अत्याचार और उत्पीड़न पर सदाचार और भक्ति की जीत का प्रतीक है। समय के साथ, यह त्योहार रंगों की बौछार, चंचल उल्लास और सामुदायिक दावत द्वारा चिह्नित एक खुशी के अवसर के रूप में विकसित हुआ। हालाँकि, इसका उत्सव भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक गतिशीलता और शक्ति संरचनाओं को भी दर्शाता है, जिसमें जाति, वर्ग और लिंग पदानुक्रम शामिल है।

श्रमिक आंदोलन और एकजुटता :

श्रमिक आंदोलन में निहित भारतीय मजदूर संघ, कृषि, विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करता है। भारतीय मजदूर संघ के लिए, होली श्रमिकों के बीच एकजुटता के बंधन की पुष्टि करने, उनके सामूहिक संघर्षों और उपलब्धियों का जश्न मनाने और सम्मान, न्याय और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं की तलाश में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने का अवसर है।

कई कार्यस्थलों में, होली मजदूरों के लिए राहत और सौहार्द के दिन के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें क्षण भर के लिए श्रम की कठिनाइयों से बचने और सहकर्मियों और साथियों के साथ उत्सव में भाग लेने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, यह उत्सव अनौपचारिक मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और कार्यबल में महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली असमान शक्ति गतिशीलता और कमजोरियों पर भी प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ :

जबकि होली परंपरागत रूप से खुशी और उल्लास का समय है, इसका उत्सव चुनौतियों और चिंताओं से रहित नहीं है, विशेष रूप से कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और उत्पीड़न या शोषण की घटनाओं के संबंध में। भारतीय मजदूर संघ यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि नियोक्ता श्रमिकों को होली उत्सव में भाग लेने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करे, जो भेदभाव, जबरदस्ती या उनकी भलाई के लिए अनुचित जोखिम से मुक्त हो।

इसके अतिरिक्त, होली के दौरान सिंथेटिक रंगों, रसायनों और पानी के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय जोखिम और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं, जिससे कई स्थानों में प्रदूषण और पानी की कमी की समस्या बढ़ जाती है। भारतीय मजदूर संघ होली के दौरान पर्यावरण–अनुकूल और टिकाऊ प्रथाओं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग, जल संरक्षण उपायों और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन पहल को बढ़ावा देने की वकालत करता है।

इसके अलावा, होली मौजूदा सामाजिक असमानताओं और तनावों को भी बढ़ा सकती है, खासकर जाति और धार्मिक आधार पर। भारतीय मजदूर संघ समावेशी समारोहों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है जो विविधता का सम्मान करते हैं, अंतर–धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, और जाति–आधारित भेदभाव और बहिष्करण प्रथाओं को चुनौती देते हैं।

सामुदायिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण :

चुनौतियों के बावजूद, होली सामुदायिक सहभागिता, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के अवसर प्रस्तुत करती है। भारतीय मजदूर संघ जमीनी स्तर की पहल को प्रोत्साहित करता है जो स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने, सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए होली की भावना का लाभ उठाता है। समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जैसे सफाई अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और कौशल–निर्माण कार्यशालाएँ हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाती हैं और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करती हैं।

इसके अलावा, होली श्रम अधिकारों, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर वकालत और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय मजदूर संघ आपसी सम्मान, संवाद और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने, श्रमिकों, नियोक्ताओं और नीति निर्माताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अभियान आयोजित करता है।

भारत में होली का उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक गतिशीलता और श्रम वास्तविकताओं के जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। भारतीय मजदूर संघ श्रमिक आंदोलन के लिए, होली न केवल एक उत्सव के अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसके माध्यम से कार्यस्थल अधिकारों, सामाजिक न्याय और सामुदायिक एकजुटता के मुद्दों की जांच और समाधान किया जा सकता है। समावेशी और टिकाऊ उत्सवों को बढ़ावा देकर, श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करके और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, भारतीय मजदूर संघ एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने में योगदान देता है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता होली की खुशियों और अपने श्रम के फल में पूरी तरह से भाग ले सकता है। ❐

आयुध निर्माणी दिवस का स्मरणोत्सव–
भारत की औद्योगिक ताकत को श्रद्धांजलि

– राम कुमार शर्मा
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य

परिचयः

भारत में प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाने वाला आयुध निर्माणी दिवस, देश के आयुध कारखानों के योगदान और उपलब्धियों का सम्मान करने के दिन के रूप में विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और स्वदेशी विनिर्माण कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित, ये कारखाने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अन्वेषण में, हम आयुध निर्माणी दिवस के बहुमुखी आयामों पर प्रकाश डालते हैं, इसकी ऐतिहासिक जड़ों का पता लगाते हैं, भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं, और इन महत्वपूर्ण संस्थानों के पीछे कार्यबल के लचीलेपन और नवाचार का जश्न मनाते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

भारत की आयुध फैक्टरियों का इतिहास 19वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान का है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1801 में कोसीपोर, कोलकाता में पहली आयुध फैक्टरी की स्थापना की थी। इन फैक्टरियों को शुरू में जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सेना और औपनिवेशिक विस्तार प्रयासों का समर्थन करती है। समय के साथ, आयुध कारखानों का नेटवर्क भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, जिससे हथियारों, गोला–बारूद और सैन्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन हुआ।

1947 में भारत की आजादी के बाद, नवगठित सरकार ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन के रणनीतिक महत्व को पहचाना और देश के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की यात्रा शुरू की। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की स्थापना 1979 में देश भर में आयुध कारखानों के कामकाज की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना था।

महत्व और योगदानः

आयुध निर्माणी दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों और तकनीकी नवाचार में भारत के आयुध कारखानों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। ये कारखाने छोटे हथियार, तोपखाने, बख्तरबंद वाहन, गोला–बारूद, विस्फोटक और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा घटकों सहित विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आयुध कारखानों की स्वदेशी उत्पादन क्षमताएं न केवल आयात पर निर्भरता को कम करती हैं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा उपकरणों की लागत–प्रभावशीलता, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुकूलन में भी योगदान देती हैं। इसके अलावा, रक्षा विनिर्माण का स्थानीयकरण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है, जिससे देश में आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास होता है।

सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, आयुध कारखाने आपदा प्रबंधन, कानून प्रवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास सहित नागरिक क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए भी अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करते हैं। उनकी बहुमुखी विनिर्माण क्षमताएं उन्हें रेलवे उपकरण और औद्योगिक मशीनरी से लेकर चिकित्सा उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने में सक्षम बनाती हैं, जो राष्ट्रीय विकास और लचीलेपन में योगदान देती हैं।

कार्यबल उत्कृष्टता का जश्न मनानाः

भारत के आयुध कारखानों के केंद्र में समर्पित और कुशल कार्यबल हैं जिनमें इंजीनियर, तकनीशियन, कारीगर और सहायक कर्मचारी शामिल हैं जो रक्षा उपकरणों की परिचालन तैयारी और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आयुध निर्माणी दिवस देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में उनकी प्रतिबद्धता, सरलता और व्यावसायिकता का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है।

आयुध कारखानों का कार्यबल नवाचार और लचीलेपन की भावना का उदाहरण देता है, विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उत्कृष्टता की खोज में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करता है। उनके सामूहिक प्रयास रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और मान्यता अर्जित करने में योगदान करते हैं।

इसके अलावा, आयुध निर्माणी दिवस कारखाना श्रमिकों के परिवारों के बलिदान और योगदान को स्वीकार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो देश की सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा के प्रयासों में अपने प्रियजनों को अटूट समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उनका लचीलापन और एकजुटता भारत के आयुध विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए अभिन्न अंग हैं।

आगे देख रहा :

जैसे–जैसे भारत आत्मनिर्भरता और अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आयुध कारखानों की भूमिका अपरिहार्य बनी हुई है। आयुध निर्माणी दिवस देश की संप्रभुता की रक्षा करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में इन संस्थानों की स्थायी विरासत और निरंतर प्रासंगिकता की याद दिलाता है।

उभरती सुरक्षा चुनौतियों और भू–राजनीतिक गतिशीलता के सामने, भारत के आयुध कारखानों को गुणवत्ता, दक्षता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सशस्त्र बलों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन और नवाचार करना चाहिए। निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक साझेदारी भारत के रक्षा औद्योगिक आधार की क्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ा सकती है, जिससे अधिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

निष्कर्ष :

आयुध निर्माणी दिवस भारत की औद्योगिक ताकत, लचीलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह उन लोगों की विरासत का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने आयुध कारखानों की स्थापना और विकास में योगदान दिया है और इन महत्वपूर्ण संस्थानों के पीछे कार्यबल के समर्पण और विशेषज्ञता को मान्यता दी है। जैसे–जैसे भारत आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, देश की आयुध फैक्ट्रियां इसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए इसकी आकांक्षाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

मेरी कामना

– दत्तोपंत ठेंगड़ी

सुनता और पढ़ता आया हूँ कि इच्छाएं 'इत्यलम' कहना नहीं जानती और चाहों का चक्र कभी नहीं थमता । मगर मैं तो कामनाओं के वृत्त में 'दौड़ने का रसिक हूँ। पाने का अपना आनन्द होता होगा, किन्तु चाहने का सुख भी छोटा नहीं है, यदि चाह छोटी न हो । इसलिए चाहता हूँ ।

मनुष्य को पंगु और बौना बनाने वाली गरीबी मिटे,
जीविका के लिए जीवन रेहन न रखना पड़े,
रोटी इन्सान को न खाये।।

मशीनें श्रम की कठोरता को घटायें,
उत्पादकता को बढ़ायें,
मगर वे श्रम का अवसर न छीनें,
न आदमी को अपना पुर्जा बना पायें ।।

पृथ्वी का दोहन विवेक पूर्वक हो,
प्रकृति से द्रोह न किया जाये ।।

दरिद्रता, दैन्य व अत्याचार को मिटाने का वीरावेश भड़के,
परन्तु क्रूरता बहादुरी का मुखौटा पहनकर न घूमे।।

समाज और व्यक्ति राष्ट्र और विश्व में परस्पराश्रय हो,
परस्पर विरोध नहीं ।।

धनी–निर्धन, विद्वान–अनपढ़ और
शासक–शोषित का द्वैत मिटकर अद्वैत उभरे।।

सुख विलासिता का,
सादगी रसहीनता और मनहूसियत का,
तप वर्जनाओं का,
कला कृत्रिमता का पर्यायवाची न बने ॥।

सत्य संख्या में न दब जाये,
सौन्दर्य अलंकरण में न छिप जाये,
विज्ञान हिंसा का दास न हो ।।

जीवन और जगत् पर प्रकाश,
आनन्द और करुणा का राज्य हो ।।
इन चाहों के चक्कर में मैं युग–युग भटकने को तैयार हूँ ।

साभार :– दत्तोपंत ठेंगड़ी जीवन–दर्शन

शहीद दिवस

आज देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते–हंसते न्यौछावर करने वाले तीन वीर सपूतों का शहीद दिवस है। 23 मार्च यानि क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने वा गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है।

उनके उज्ज्वल चरित्रों को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे मानव भी इस दुनिया में हुए हैं, जिनके आचरण किंवदंति हैं। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उनके बाद अब किसी के लिए संभव न होगी। श्आदमी को मारा जा सकता है उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है।श बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून–खराबा न हो तथा अंग्रेजों तक उनकी आवाज पहुंचे।

निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला।

यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन व अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे।

भगत सिंह : भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7.23 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई।

शहीद सुखदेव : सुखदेव का जन्म 15 मई, 1907 को पंजाब को लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास–पास ही रहने से इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी, साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सांडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था।

शहीद राजगुरु : 24 अगस्त, 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में राजगुरु का जन्म हुआ। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे।

पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर, 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सांडर्स को गोली मार दी थी और खुद ही गिरफ्तार हो गए थे। ❐

WOMEN'S EMPOWERMENT

Introduction:

India, a land of diversity and complexity, has a rich tapestry of women's power that intertwines tradition, progress, and ongoing challenges. Across history, Indian women have played pivotal roles in shaping cultural, social, economic, and political landscapes. However, entrenched patriarchal norms, systemic inequalities, and cultural barriers have hindered their full empowerment. In this comprehensive exploration, we delve into the multifaceted dimensions of women's power in India, examining historical legacies, contemporary realities, and pathways to empowerment.

Historical Legacies:

Indian history is replete with stories of powerful women who defied societal norms and left indelible marks on culture and governance. From ancient times, figures like Rani Lakshmibai of Jhansi, Razia Sultana, and Ahilyabai Holkar demonstrated leadership, valor, and resilience in defending territories and fostering social welfare.

The Vedic era witnessed the prominence of women scholars and seers like Gargi and Maitreyi, who engaged in philosophical discourse and contributed to religious texts. During the Mauryan Empire, Queen Didda of Kashmir and Queen Chandragupta Maurya wielded political authority and governed territories.

Medieval India saw the emergence of powerful queens and rulers such as Raziya Sultan, who ascended to the throne of Delhi Sultanate, challenging gender norms in governance. Rajput warrior queens like Rani Karnavati and Rani Padmini displayed courage and valor in defending their kingdoms against external invasions.

Colonialism brought new dynamics to women's power in India, with movements for social reform and women's education gaining momentum. Figures like Raja Ram Mohan Roy and Jyotirao Phule advocated for women's rights and abolition of social evils like Sati and child marriage.

Contemporary Realities:

Despite historical legacies of women's empowerment, contemporary India grapples with persistent challenges and inequalities. Gender disparities persist in various spheres, including education, employment, healthcare, and political representation. While strides have been made in increasing female literacy and access to education, rural and marginalized communities still face barriers to quality schooling and vocational training.

Smt. Sudha Shukla
President
DMSRDE Emp. Union

Economic empowerment remains a critical issue, with women disproportionately represented in informal sectors and facing wage gaps and limited access to credit and property rights. The patriarchal structure of society often restricts women's mobility, financial autonomy, and participation in decision-making processes.

Gender-based violence continues to be a pervasive issue, with high rates of domestic violence, sexual harassment, trafficking, and dowry-related crimes. Despite legislative measures and awareness campaigns, implementation gaps and social stigma hinder survivors from seeking justice and support.

Political participation and representation remain skewed, with women constituting a minority of elected representatives at all levels of government. While initiatives like the Panchayati Raj system have increased women's participation in local governance, systemic barriers such as patriarchy, casteism, and political dynasties persist.

Pathways to Empowerment:

Empowering women in India requires a holistic approach that addresses systemic inequalities, changes cultural attitudes, and fosters inclusive development. Education plays a pivotal role in breaking the cycle of poverty and empowering women with knowledge, skills, and confidence. Investing in girls' education, particularly in rural and marginalized communities, enhances their opportunities for economic independence and leadership roles.

Economic empowerment initiatives such as microfinance, skill development programs, and entrepreneurship training enable women to generate income, access financial services, and contribute to household and community development. Promoting women's participation in formal employment sectors, leadership positions, and decision-making bodies is essential for challenging gender stereotypes and fostering inclusive growth.

Legal reforms and enforcement mechanisms are crucial for protecting women's rights and addressing gender-based violence. Strengthening laws against dowry, domestic violence, sexual harassment, and trafficking, and ensuring access to justice and support services for survivors, are paramount. Sensitizing law enforcement agencies, judiciary, and communities to gender issues and human rights principles fosters a culture of accountability and respect for women's dignity and autonomy.

Social and cultural transformation requires challenging patriarchal norms, stereotypes, and discriminatory practices through education, media, and community mobilization. Promoting positive representations of women in media, literature, and popular culture, and engaging men and boys as allies in gender equality efforts, fosters more inclusive and egalitarian attitudes.

Healthcare interventions, including maternal health services, reproductive rights, and nutrition programs, are integral to women's well-being and empowerment. Ensuring access to quality healthcare, family planning services, and reproductive rights education empowers women to make informed choices about their bodies, health, and future.

Conclusion:

Empowering women in India is not merely a matter of social justice but a strategic imperative for sustainable development and inclusive growth. By addressing systemic inequalities, fostering inclusive policies, and challenging cultural norms, India can unlock the full potential of its women as agents of change, progress, and prosperity. Through concerted efforts across sectors and stakeholders, India can realize its vision of a more equitable and empowered society, where every woman can thrive and contribute to nation-building.

❐

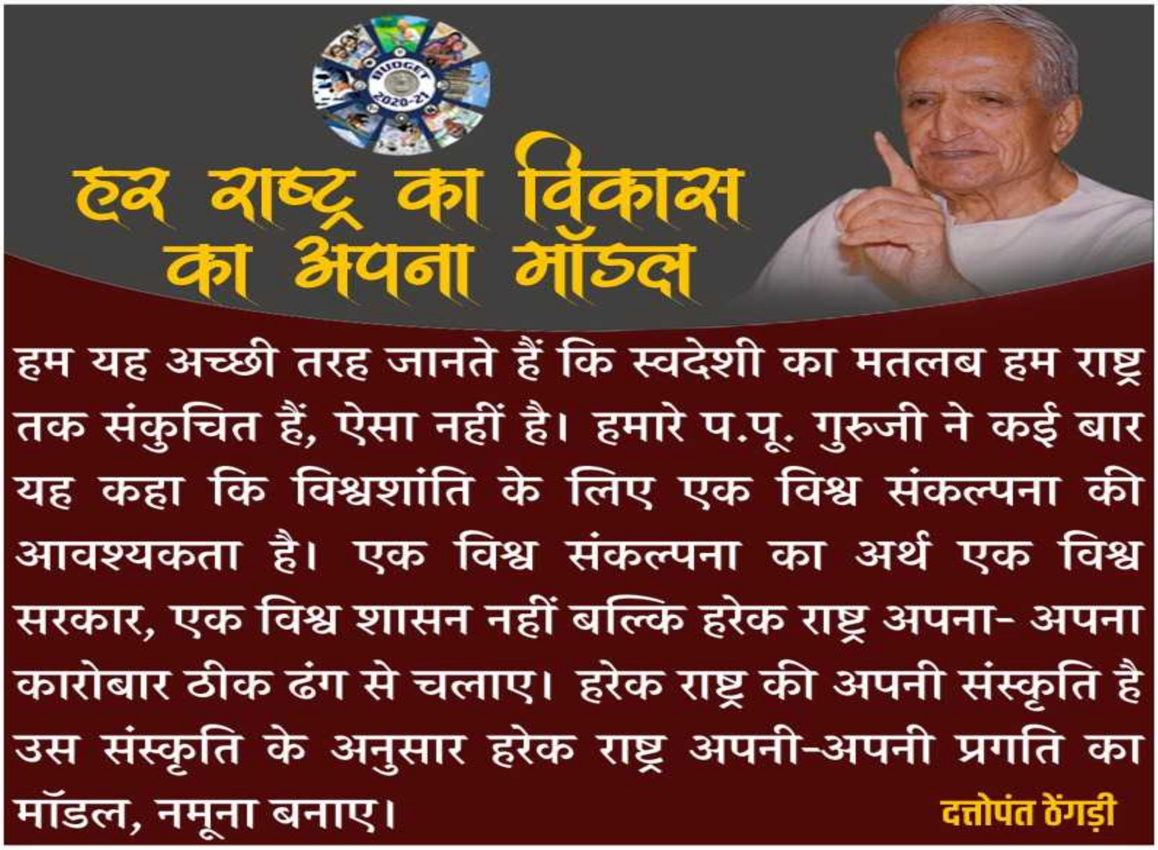

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

No.6/8/2023 -Pers.Policy (Deputation/Re-employment) Pt.XV, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel & Training New Delhi, dated 15 March, 2024

Subject: Deputation of Group 'A' Officers of the Central Government to State Governments/UTs—Modification in guidelines - regarding.

The undersigned is directed to invite attention to the consolidated guidelines/instructions uploaded on the website of DOPT with regard to regulation of terms and conditions governing deputation / foreign service of employees to/from Central government including instructions/guidelines to be followed in connection with transfer on deputation/foreign service of Central Government employees to ex-cadre posts under Central Government /State government /Union Territories administration / Public Sector Undertakings / Autonomous Bodies / Statutory Bodies / Universities / Local Bodies etc. and vice versa.

2. Attention is also drawn to para 1.3 of this Department's **OM No.AB**- 14017/2/2007-Estt (RR) dated 29.02.2008 indicating the provisions regulating tenure and procedure of appointment on deputation /foreign service for members of Organized Group A and Group B Services of the Central Government.

3. In consonance with the provisions governing inter-cadre deputation of officers belonging to the All India Services and in partial modification of the existing instructions, deputation of Group 'A' officers of the Central Government to ex-cadre posts under a State Government/UT Administration including PSUs/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/ Universities / Local Bodies under the States / UT Administration, would be regulated as per the following procedure, to be strictly adhered to by the Cadre Controlling Authorities (CCAs) of Lending Organisations:

(i) All such cases shall be submitted for consideration and approval of the **Appointments Committee of the Cabinet (ACC).**

(ii) Such deputation will be available to the officers only after completion of nine years of service in parent Cadre and before reaching Level 14 of the Pay Matrix in the Parent Cadre.

(iii) The 1st July of the batch year is to be considered as the starting date of calculating length of service for the purpose of counting nine years of eligibility of the officers seeking deputation. In case of promotee officers, nine years of eligibility service for seeking such deputation shall be counted from the 1St July of the year of allotment/induction into Group 'A' service or promotion to Group 'A' post.

(iv) A request for such deputation will be entertained only if it is forwarded by the Cadre Controlling Authority along with NOC/Consent of the borrowing State Government.

(v) All such cases of deputation will be initially restricted to three years, extendable by two more years after review. Where the initial period of deputation is for less than three years, continuation of the officer on deputation basis beyond the initial period, shall be treated as a case of extension of that deputation, requiring prior approval of the ACC.

(vi) The total allowable period of such deputation to any State Government / LIT Administration including PSUs / Autonomous bodies/Statutory Bodies! Universities / Local Bodies in the States / UT Administration in the entire career of the officer shall be restricted to five years. No extension of deputation beyond five years shall be allowed.

(vii) The officers who are already on deputation and reached Level 14 of the Pay Matrix in the Parent Cadre, while on deputation, may be allowed to complete their full term.

(viii) A request for extension of deputation after the initial period of deputation (subject to restriction of the overall tenure of deputation of five years) will be entertained only if it is forwarded by the Cadre Controlling Authority along with NOC of the borrowing State Government, with cogent reasons and at least three months prior to the expiry of the period of deputation. In case no specific approval of the Central Government for extension is received within the period for which deputation was originally valid, the officer shall have to be relieved positively and immediately on completion of the original tenure.

(ix) In cases where an officer has completed the approved period of deputation, it would be made clear to the officer and to the Cadre Authorities concerned that adverse notice will be taken at the time of empanelment and promotion of the officer if the officer continued on such deputation beyond the approved period of deputation.

(x) The deputation is valid only for the period for which it is allowed by the Central Government and any

extension is neither automatic nor should be presumed merely on the ground that the Cadre Authorities concerned or officer or both made a request for extension. As such, the officer shall be entitled to draw salary etc. in the borrowing State Government to which he/she has been deputed only for the period for which he/she has been allowed deputation by the Government of India. The officer shall not be entitled to draw salary etc. after expiry of the period of deputation. An officer on such deputation shall relinquish charge and get himself/herself relieved on the last day of his/her deputation, if no orders extending his/her deputation by the concerned Cadre Controlling Authority are received in the borrowing State Government.

(xi) An officer who does not handover charge at the end of the approved period of deputation will be immediately liable to disciplinary action and break-in-service for the period beyond the approved date. All orders of deputation will carry endorsement to this effect. Further, an endorsement will also be made to the Accountant General of the State/UT Administration or competent authority concerned to stop payment of salary to the officer beyond the approved period of deputation. In case of overstay, the officer will be immediately liable to disciplinary action and break-in-service for the period beyond the approved date.

(xii) Copies of all deputation orders must be marked to/served on the officer concerned along with State Government/UT/borrowing Organisation and others concerned.

(xiii) In the event the officer overstays for any reason whatsoever, he/she is liable for disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include the period of overstay not being counted towards service for the purpose of pension and any increment due during the period of overstay being deferred with cumulative effect, till that date on which the officer rejoins in his parent organisation.

(xiv) The State/UT/borrowing Organisations are advised to relieve the officer promptly on the last date of completion of the deputation tenure without fail unless the competent authority in the Central Government extends the period of deputation in writing prior to its date of expiry.

(xv) Grant of leave to officer on completion of their tenure of deputation: On reversion from such deputation, the officers concerned might be allowed leave not exceeding two months by the borrowing State Government where the officer was on deputation and that the officer concerned should apply for further leave to his/her parent cadre. Further, such leave is debitable from the leave account of the officer.

(xvi) Cooling off period:

a) If the deputation is to North-East States, the cooling off period would be waived off

b) Thus, an officer would be allowed to go on deputation to a North-East State directly on completion of existing deputation in a post under the Central Government, without cooling off

c) Conversely, an officer can proceed on another deputation to a post under the Central Govt. directly after serving a full term of deputation in a North-East State for five years, without undergoing mandatory cooling off period, on the basis of the officer's own request and subject to cadre clearance.

d) In all other cases, 'cooling off' requirement shall be governed by the provisions contained in 'Consolidated Deputation Guidelines' issued vide OMNo.AB-14017/2/07- Estt(RR) dated 29.02.2008.

(xvii) Relaxation of policy guidelines:

a) The cases where relaxation of any of the provisions of these guidelines are required will be put up to a Committee for a decision as to whether the proposal may be submitted to the ACC for its consideration, in relaxation of existing guidelines.

b) Composition of Committee: The composition of the Committee, constituted to consider such cases of Group 'A' Officers of the Central Government, where relaxation of any of the provisions of the policy/guidelines are required, would be as under:

1	Secretary to Government, Department of Personnel & Training.	Chairman
2	Establishment Officer & Additional Secretary, Department of Personnel & Training.	Member
3	Secretary of the Administrative Ministry/ Department concerned.	Co-opted Member
4	Additional Secretary / Joint Secretary in charge of Pers Policy Division, Department of Personnel & Training	Member Secretary

c) The Committee shall consider all such cases of deputation and give its recommendations on the need and justification of such deputation.

(xviii) In terms of clause (v) of this O.M., the aforementioned Committee shall review all cases seeking extension of deputation beyond 3 years, and that only those cases recommended by the Committee

for extension of deputation beyond 3 years, would be placed before the ACC for consideration. As a one-time measure, the aforesaid Committee shall also review the present cases of deputation to State Governments/UT Administration PSUs! Autonomous bodies/Statutory Bodies! Universities/Local Bodies under the States/UT Administration where the remaining tenure of the officer is six months or more. The Committee after review shall give its recommendation for continuation of the officer till the end of term of deputation. Such cases shall thereafter also be submitted for the consideration and approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

(xix) The Cadre Controlling Authorities shall consider all cases of deputation of Group 'A' officers of Central Government to State Governments/UT including PSUs / Autonomous bodies/Statutory Bodies / Universities / Local Bodies under the States/UT Administration keeping in view the aforementioned guidelines and submit the same, along with the approval of the Minister in Charge, for consideration and approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

4. Provisions contained in para 1.3 of this Department's OM No.AB-14017/2/2007- Estt (RR) dated 29.02.2008, to the extent they govern the deputation of Group 'A' officers of the Central Government to ex-cadre posts under State Governments/Union Territories including PSUs! Autonomous bodies/Statutory Bodies! Universities/Local Bodies in the States/UT Administration stand modified accordingly. All other instructions !guidelines consolidated vide DOPT's OM dated 08.09.2022 and OM dated 29.02.2008 shall remain unaltered.

5. These guidelines shall be applicable with immediate effect.

6. Hindi version will follow. ❐

No. 1/1/2024-E-II (B), Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure New Delhi, dated 12 March, 2024

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees- effective from 01.01.2024.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4/2023- E-II (B) dated 20" October, 2023 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 4% January, 2024.

2: The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7" CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5: The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2024.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India. ❐

No, A-27012/01/2023-Pers. Policy(Allowance), Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training New Delhi, dated 14 March, 2024

Subject: Reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy in accordance with New Education Policy 2020.

The Government of India has implemented the New Education Policy (NEP) 2020. Keeping in view the NEP 2020, the following modification have been carried out in the para 2(p) of O.M. No. A-27012/02/2017-Estt(AL) dated 17-07-2018:-

> "The CEA and Hostel Subsidy is admissible, in respect of children studying from three classes before class one to 12" standard (irrespective of nomenclature of class) and also for the initial two years of a diploma/certificate course from Polytechnic /ITI/ Engineering College, if the child pursues the course after passing 10" standard and the Government servant has not been granted CEA/hostel subsidy in respect of the child for

studies in 11" and 12" standards."

2. Further, it has also been decided to grant one time relaxation for reimbursement of CEA/Hostel Subsidy to those Government employees whose children have to repeat one additional class due to implementation of New Education Policy 2020.

3. The OM shall come in to effect from the academic year 2023-24 onwards.

4. This issues with the approval of competent authority. ❐

F. No.12/4/2020-JCA Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, (Department of Personnel & Training), Establishment (JCA) Section New Delhi, dated 14 March, 2024

Subject: Subject: Declaration of Holiday on 14" April, 2024— Birthday of Dr. B.R. Ambedkar.

It has been decided to declare Sunday, the 14% April 2024, a holiday on account of the birthday of Dr. B.R. Ambedkar, for all Central Government Offices including Industrial Establishments throughout India.

2. All Ministries/Departments of Government of India may bring the above decision to the notice of all concerned.

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. UPSC / CVC/C&AG / National Commission for Linguistic Minorities / National Commission for Scheduled Castes/National Commission for Scheduled Tribes/National Commission for Minorities/President's Secretariat / Vice President's Secretariat/Supreme Court / High Court / Central Administrative Tribunal / Central Information Commission/Prime Minister's Office / Cabinet Secretariat / Election Commission of India / National Human Rights Commission / National Commission for Women/National Commission for Backward Classes/Niti Ayog / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat.
3. All Sections / Officers in the Ministry of Personnel, PG & Pensions
4. All attached Offices / Subordinate Offices / Autonomous bodies of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions.
5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C Ferozeshah Road, New Delhi (with 10 spare copies}
6. Reserve Bank of India, Parliament Street, New Delhi.
7. Chairman / Secretaries, Central Government Employee Welfare Coordination Committees.
8. PIO, PIB, Shastri Bhavan, New Delhi, with the request that necessary publicity may be given in this regard.

9, Facilitation Centre, DOP&T (20 copies)

10. NIC (DOP&T) with the request to place this O.M. on the Website of DOPT.(www.persmin.nic.in ❐

F.NO. 3/1/2024-e-HRMSv2.0, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training), New Delhi, dated 20 February, 2024

Subject: Timelines for Service Delivery through e-HRMS 2.0 Portal-reg.

The undersigned is directed to state that the e-HRMS 2.0 portal facilitates seamless digital working environment and streamlines the disposal mechanism of various human resource services as expeditiously as possible. Any kind of applications with respect to leave, claims and reimbursements etc that are provided to the Government employees as per the applicable and extant rules/guidelines/instructions can now be disposed of through various modules of e-HRMS in an easy and transparent manner at the click of a button.

2. In order to make the said Portal more employee centric and as a Good Governance initiative, simplification of processes has been attempted in the HR Management System, wherever applicable. After various rounds of discussions and lot of deliberations, it has been decided to fix certain timelines for the simple processes for the ease and benefit of the employees.

3. In this connection, this is to inform all the Ministries/Departments/Organization (MDOs), that auto approvals and escalations to next level is being incorporated for specified timelines for the following services/modules provided through e-HRMS portal for effective implementation of e-HRMS 2.0:

i) Leave Module;

ii) Reimbursement & Allowances;

iii) Advances and LTC module.

The attached Annexures I, II,III are enumerative and descriptive for the reference and understanding of all.

4. This issues with the approval of Secretary (P).

1. Timelines with regard to leaves due and admissible and Study Leave:

A. Where Admin is not involved in approval channel :

S No.	Type of Leave	No. of Days (leave)	Proposed time-lines for decision at R.O./C.O. level		Total Time	e-HRMS Division's Remark Existing rules
			RO	CO		
1	Casual Leave	<3	3	--------	3 working days (Auto approval)	**Reason:** It should not normally be granted for more than 5 days at a time. This is not any regular kind of leave. The absence in this category may be either anticipated or not| anticipated. Considering the' nature of CL, suitable provision for auto-lapproval/forward may be inserted on the e-HRMS portal for CL. **Implementation:** If the employee requests Casual Leave up to 3 days, then the Reporting Officer should take appropriate decision on the request within 3 working days otherwise the leave shall be deemed approved. Further, if the period of casual leave exceeds 3 days (upto 5 days), the request would be automatically forwarded to the CO if no decision is taken at RO level for 3 working days. The Controlling Officer needs to take a decision on the request within next 03 working days otherwise the leave request shall be deemed approved.
		<3 and <=5	3	3	6 working days (Auto forwarding & Auto Approval)	
2	EL	<5	3	3	6 working days (Auto forwarding & Auto Approval)	Maximum Accumulation of EL: 300/15. **Reason:** If the employee requests for EL for a short period of 5 days (excluding prefix/suffix of holidays), a decision on the same in a maximum of 6 working days would be fair. Hence, auto-forward after 3 working days at RO level and deemed approval after 3 working days at CO level is recommended. If the employee requests EL for more than 05 days, it affects the office work for a longer period. As per the existing guidelines, the maximum EL grant limit is 180 days at a time. Therefore, automatic approval is not convenient in this situation. However, auto forward facility may be included at the RO level to avoid delay in taking decisions in this regard.
		5+	3	3	6 working days (Auto forwarding & Auto Approval)	
						Implementation: If the employee requests EL for a shorter period i.e. up to 05 days, an appropriate decision (approve / disapprove / forward) on the request can be taken by the concerned R.O./C.O. in a time bound manner. The request shall be auto forwarded to C.O. if no decision is taken at R.O. level for 3 working days. Further, if no decision is taken at C.O. level, then it shall be deemed approved land balance updated. If the period of EL exceeds 05 days, the RO has to take appropriate decision on the request within 03 working days of receipt of the request otherwise the request should be automatically forwarded to the CO. The Controlling Officer has to take a decision on the request within next 03 working days otherwise it will be part of the pendency report.
3	HPL (only in case of private affairs)	<5	3	3	6 working days	**Rule:** may be granted on medical certificate or on private affairs. **Reason:** as mentioned for EL. **Implementation:** same as EL
			3	3	6 working days	

B. Where Admin is involved in approval channel:

S No.	Type of Leave	No. of Days (leave)	Proposed time-lines for decision at R.O./C.O. level			Total Time	e-HRMS Division's Remark Existing rules
			RO	CO	Admin		
4	Comm-uted Leave (on **Medical** certi-ficate	--------	3	3	9	15	**Rule:** not exceeding half the amount of haf pay leave due may be granted. When commuted leave the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due. **Reason :** The commuted Leaves are granted on production of medical Certificate. Admin Division check and verify that the Medical Certificate and other documents attached for this purpose are in line with existing guidelines. Further, the request for commuted leave is submitted after the employee returns from leave taken for Medical reasons. Therefore, decision can be taken on requests for Commuted leaves in a time bound manner. Timelines for each level involve in the approval channel may be inserted for this purpose. **Implementation :** An appropriate decision should be taken within 03 days of receipt of the request by the R. O. otherwise request should be automatically forwarded to the CO. The CO has to take a decision on the request within next 03 days otherwise it should be automatically forwarded to Admin. No auto-approval.
5	Comm-uted Leave (for an approv-ed **Course of Study**)	--------	3	3	9	15	Rule: a maximum of 180 days **Reason:** The Commuted Leaves are granted for an approved course of study certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority. Admin Division has to check and verify the details in this regard. **Implementation :** as mentioned for Commuted leave on Med. Certificate at point 04 above.

6	Leave not due (on **medical** certifi-cate)	--------	3	3	9	15	**Rule:** Leave Not Due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter. Leave Not Due shall be debited against the half pay leave the Government servant may earn sbsequently. **Reason :** same as mentioned against Commuted Leave (on Medical Certificate). **Implementation :** same as mentioned against Commuted Leave (on Medical certificate).
7	EOL (only in case of prior appro-val)	--------	3	3	9	15	Rule : **EOL** Granted in **special circumtances.** **Reason:** EOL are granted when no other leave is admissible or Govt. Servant applies in writing for grant of EOL. Sometimes EOL are also granted to regularize the service period of employee from back date. In case of prior approval, appropriate decision can be taken by the concerned RO/CO/Admin in a time bound manner, therefore, timeline for EOL may be framed. **Implementation :** An appropriate decision should be taken within 03 days of receipt ofthe request by the R. O. otherwise the request should be automatically forwarded to CO. The CO hs to take a decision on the request within next 03 days otherwise it should be automatically forwarded to Admin. NO auto-approval.
8	Study Leave	--------	3	3	15	21	**Reason : Study Leaves** are forwarded to Admin Division through R.O. and C.O. Admin Division has to check and verify the relevant details. Admin division also obtains IFD's Concurrence. Administrative approval of Competent authority, Cadre Clearance for this purpose. **IMplementation :** An appropriate decision should be taken within 03 days of receipt of the request should be automaticaly forwarded to the CO. The CO has to take a decision on the request within next 03 days otherwise it should be automatically forwarded to Admin. No auto approval.

II. Timelines for Reimbursement Allowance :

S No.	Module	Proposed timelines for decision				e-HRMS Division's Remark
		L-1	L-2	Approval + Saction Order	Total Time	
1	Newspaper	3	3	3	9	**Reason :** The practice of getting of monthly reimbursement of Newspaper on production of Newspaper bills has been abolished. A certificate to the effect that expenditure has been incurred on newspaper shall be provided by the officer's on half yearly basis (Jan to June or July to Dec) to the office for reimbursement . It appears that an appropriate decision on the newspaper reimbursement request may be taken in a time bound maner. Therefore, a time limit should be set for this purpose. **Implemantation :** An appropriate action should be taken within 03 days of receipt of the request by the dealing hand (L-1). The request should be processed till issue of sanction order within 9 days of its receipt otherwise it will be part of the pendency report.
2	Telephone	3	3	3	9	**Reason :** The amount shall be reimbursed on submission of bills/receipt by the concerned officer (as per entitlement). It appears that the request may be settled in a time bound manner. **Implemantation :** same as mentioned to Newspaper Reimbursement.
3	CEA	5	3	3	11	The amount of CEA is fixed. Govt. Servant shoild produce a certificate for this purpose. The request may be disposed of in a time bound manner. **Implementation :** An appropriate action should be taken within 03 days of receipt of the request by the dealing hand (L-1). The request should be processed till issue of sanction order within 11 days of its receipt otherwise it will be part of the pendency report.
4	**Medical**	5	3	3	11	**Reason :** The request of Medical reimbursement may be settled in a time bound manner. Therefore, timeline for this purpose may be framed. **Impl;emantation :** Same as CEA.

III. Timelines for Advaces and LTC Module -

A. LTC Module - The system LTC request only if leave(s) for LTC has been sanctioned before submitting the LTC request.

S No.	Module	Proposed timelines for decision				DOPT's Remark
		L-1	L-2	Approval + Saction Order	Total Time	
1	Leave Encashment	4	2	2	8	A Government servant may be permitted to encash earned leave up to ten days at the time of availing of LTC. **Implementation:** An appropriate action should be taken within 04 days of receipt of the request by the Dealing hand/L-1. The request should be processed till issue of sanction order within 8 days of receipt of the request otherwise it will be part of the pendency report.
2	LTC request (with or with-out Advance	4	2	2	8	**Implementation :** Sace as leave Encashment
3	LTC Claim	4	2	2	8	**Implementation :** Sace as leave Encashment

b. Advances

S No.	Module	Proposed timelines for decision				DOPT's Remark
		L-1	L-2	Approval + Saction Order	Total Time	
1	Leave Encashment	5	3	3	11	**Implementation:** An appropriate action should be taken within 05 days of receipt of the request by the Dealing hand/L-1. The request should be processed till issue of sanction order within 8 days of receipt of the request otherwise it will be part of the pendency report.
3	HBA	5	3	3	11	**Implementation :** aS IN POINT 1.

❒

No. 36039/1/2019-Estt.(Res.-II) Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Establishment (Res) Section New Delhi, dated 15 March, 2024

Subject: Modification/Revision in instructions regarding authorities competent to issue Caste/Tribe/Community certificates in respect of SC/ST/OBC and Income and Asset Certificates in respect of EWS -reg.

I am directed to state that this Department has issued instructions to the State Government/U.T Administration from time to time prescribing the authorities of the State Governments /U.T. Administrations, who are competent to issue Caste/Tribe/Community certificates in respect of SC/ST/OBC and Income and Asset Certificates in respect of EWS. However, it has come to the notice of this Department that in some States, such Certificates have not been issued by the authorities prescribed by this Department, leading to avoidable hardship for the candidates.

2. In this regard, it is stated that the responsibility for issue and verification of caste/community certificate lies with the concerned State Government/UT Administration. The Hon'ble Supreme Court, vide its judgement in the matter of 'Kumari Madhuri Pati! vs Add!. Commissioner', has already laid down detailed guidelines to be followed by the State Government to streamline the procedure for the issuance of social status certificates, their scrutiny and their approval. The State Governments/UT Administrations are required to streamline the procedure for issuance and verification of Caste! Tribe/Community certificates in respect of SC/ST/OBC and Income and Asset Certificates in respect of EWS keeping in view the directions of the Hon'ble Supreme Court, vide its order in 'Kumari Madhuri Patil vs Addi. Commissioner'.

3. In view of the aforesaid judgement of the Hon'ble Supreme Court, it has been decided to delegate the powers to the State Governments/UT Administrations to decide the authorities competent to issue the Caste/ Tribe /Community certificates in respect of SC/ST/OBC and Income and Asset Certificates in respect of EWS candidates. The State Governments/UT Administrations shall upload on their website the details of the authorities competent to issue such Caste/Tribe/Community/Income & Asset certificate. The earlier instructions issued vide OM No. 360 12/6/88-Estt (SCT) dated 24.4.1990 and letter No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 15.11.1993 (copies enclosed) with regard to the authorities prescribed for issuance of Caste/Tribe/Community certificates in respect of SC/ST/OBC and OM No. No.36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 (copies enclosed), with regard to the authorities prescribed for issuance of Income and Asset Certificates in respect of EWS are modified to that extent.

Annexure-III

FOR DIRECT RECRUITMENT ON ALL INDIA BASIS BY OPEN COMPETITION

Model Roster for cadre strength **upto nposts**

Cader Stren-gth	Initial Recruit-ment	Replacement No.												
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th
1	UR	UR	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST
2	UR	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST	
3	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST		
4	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST			
5	UR	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST				
6	UR	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST					
7	SC	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST						
8	OBC	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST							
9	UR	EWS	UR	OBC	UR	ST								
10	EWS	UR	OBC	UR	ST									
11	UR	OBC	UR	ST										
12	OBC	UR	ST											
13	UR	ST												

Note:

1. For cadres of 2 to 13 posts the roster is to be read from entry 1 under column Cadre Strength till the last.post and then horizontally till the last entry in the horizontal row i.e. like "L"
2. All the posts of a cadre are to be earmarked for the categories shown under column initial recruitment. While initial filling up will be by the earmarked category, the replacement against any of the post in the cadre shall be by rotation as shown horizontally against the last post of the cadre.

❒

F. No.Z. 1 6025/I 2t20Z4t CGHS III, Government of India, Ministry ol Health & Familv Welfare, Oirectorate General of Central Govt. Heilth Scheme (CGHS-ttt Section) New Delhi, dated 18 March, 2024

Subject: -Ann-uar Hearth check-up at Hospitars empaneled under CGHS in respecr of CGHS pensioner beheticiarids aged ?S ViiiJana' i66r-e"j regarding.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's OM No. Z15025/36/2019/DIR/CGHS /CGHS(P) dated 19.08.2019 on the subject mentioned above regarding the entitlement of CGHS beneficiaries (Primary Card Holders) aged 75 years for Annual Health Check-up at CGHS empanelled Hospitals by obtaining the permission from the CMO incharge of CGHS Wellness Centre.

2. However, it is found that there are instances of com laints from Pensioners' Associations against non-issuance of permission by the CGHS Wellness Centre for Annual Health Check-up to the CGHS beneficiaries.

3. In view of the above, all incharge of CGHS Wellness Centres across the country are hereby advised to adhere to the instructions contained in the ibid orders and directed to issue permission to the CGHS beneficiaries accordingly.

4. This issues with the approval of the competent authority. ❒

F.No, 1-31/2020/CGHS-C&P/3 40-355, Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Central Government Health Scheme, CGHS Bhawan, New Delhi, Dated: 26.03.2024

Subject : Decentralization of Printing of CGHS-Plastic Card-reg.

In reference to the grievances received regarding delay in printing and issue of CGHS Plastic Cards to CGHS beneficiaries.

The under signed is directed to convey that matter has been examined and in order to fast track the process of card making, it has been decided to decentralize the CGHS Card Printing to every Additional Director (CGHS) of the city including Delhi. The whole process to enroll and to allocate work order to new agency for printing of CGHS-Plastic Card would be completed by 25" April, 2024.

Furthermore, for issue of duplicate CGHS card, due to loss or any other reason, Rs. 100/- shall be charged from the CGHS beneficiaries. **The specification of CGHS Cards shall continue to be decided by C&P Section located at CGHS (HQ), CGHS BHAWAN, New Delhi.**

This issue with the approval of AS & DG (CGHS). ❒

KENDRIYA VIDHYALA

SCHEDULE FOR ADMISSION (2024-25)

सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए समय-सारणी निम्नलिखित होगी :

The Admission Schedule for the Session 2024-25 will be as under:-

क्र॰सं॰ S.No	विषय- वस्तु CONTENTS	निर्धारित तिथियाँ SCHEDULED DATES
1	प्रवेश के लिए विज्ञापन Advertisement for admission	4th week of March 2024 (Latest by 31.03.2024)
2	कक्षा-1 के लिए पंजीकरण –ऑनलाइन माध्यम से Online Registration for Class-I	**01.04.2024 (Monday) 10:00 AM onwards**
3	कक्षा-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि Last date of Online Registration for Class-I	**15.04.2024 (Monday) 05:00 PM**
4	(a) Declaration of provisional lists of selected and waitlisted registered candidates सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन (b) Admission of eligible & selected candidates as per the above list in following order: (i) RTE (ii) From Service Priority Category (I and II) only (iii) Shortfall of Reservation Quota after admission in (i) and (ii)above उपरोक्त जारी सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में: i. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित ii. सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी I एवं II में से चयनित iii. उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश	**1st Provisional List on 19.04.2024 (Friday)** **2nd Provisional List on 29.04.2024 (Monday) (if seats remain vacant)** **3rd Provisional List on 08.05.2024 (Wednesday) (if seats remain vacant)**
5	शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL)प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना (कक्षा-I) यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हों तो (Offline) Extended date for the Second Notification for off line registrations for admission to be made under RTE Provisions, SC, ST and OBC (NCL), if sufficient applications were not received in online mode.	Notification on 07.05.2024 (Tuesday) Registration from 08.05.2024 (Wednesday) to 15.05.2024(Wednesday) Display of list and Admissions 22.05.2024 (Wednesday) to 27.05.2024 (Monday)
6	कक्षा-II तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण (in offline mode) (कक्षा-XI को छोडकर), कक्षा- विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में। Registration for Class-II onwards (except Class XI) - Subject (in offline mode) to availability of vacancies in a particular class.	01.04.2024 (Monday) to 10.04.2024 (Wednesday)
7	कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना Declaration of list of class II onwards.	15.04.2024 (Monday)
8	कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश। Admission for class II onwards.	16.04.2024 (Tuesday) to 29.04.2024 (Monday)
9	कक्षा-XI को छोडकर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि। Last date of admission for all classes except class XI	**29.06.2024 (Saturday)**
10	के॰ वि ॰के छात्र/ छात्रा : कक्षा-XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण **For KV students:** Registration for admission in class XI	Within 10 days after the declaration of class X result
11	के॰ वि॰ के छात्र/ छात्रा: कक्षा XI की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश **KV students:** Display of admission list & admissions for Class-XI.	Within 20 days after declaration of class X results
12	गैर के॰ वि॰ के छात्र/छात्रा: कक्षा-XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश(रिक्तियाँ होने की स्थिति में) **Non-KV students:** Registration, display of admission list & admissions in class XI (Subject to availability of vacancies)	After the admissions of KV students in class XI
13	कक्षा-XI के प्रवेश की अंतिम तिथि। Last date of admission for class - XI	30 days from the date of declaration of class-X results by CBSE

महिला दिवस पर विभिन्न रक्षा संस्थानों में
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 31 Mar. 2024 MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

AGM MEETING AT MES EMPLOYERS UNION GE CHENNAI BRANCH

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"

C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650